



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2010/आषाढ़ 1, 1932

No. 356]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2010/ASADHA 1, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 1/2010

सा.का.नि. 529(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है) की धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2010 कहा गया है।

(2) यह आदेश 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगा।

2. वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 के खंड (105) के उप-खंड (ययद) और (यययज) के प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकार प्राधिकरण के अलावा सक्षम प्राधिकारी भी शामिल है:—

- (i) आर्किटेक्ट्स अधिनियम, 1972 के अधीन गठित आर्किटेक्ट्स परिषद से पंजीकृत आर्किटेक्ट या
- (ii) इंजीनियर्स संस्थान (भारत) के साथ पंजीकृत चार्टर्ड इंजीनियर या
- (iii) शहर या पंचायत या विकास प्राधिकरण के संबंधित स्थानीय निकाय के लाइसेंस सर्वेयर, या शहर या गांव विकास प्राधिकरण के संबंधित स्थानीय निकाय के लाइसेंसधारी सर्वेयर;

परिसर के कब्जे के लिए पूर्व शर्त के रूप में किसी भी राज्य के कानून या किसी अन्य कानून के तहत आवसीय या वाणिज्यिक संपत्ति के समापन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है।

[फा. सं. 334/3/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 1/2010

G.S.R. 529(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called as the Service Tax (Removal of Difficulty) Order, 2010.

(2) This Order shall come into force on the 1st day of July, 2010.

2. For the purposes of sub-clauses (zzq) and (zzzh) of clause (105) of section 65 of the Finance Act, the expression 'authority competent' includes, besides any Government authority,—

- (i) architect registered with the Council of Architecture constituted under the Architects Act, 1972 (20 of 1972); or
- (ii) chartered engineer registered with the Institution of Engineers (India); or
- (iii) licensed surveyor of the respective local body of the city or town or village or development or planning authority;

who is authorised under any law for the time being in force, to issue a completion certificate in respect of residential or commercial or industrial complex, as a precondition for its occupation.

[F. No. 334/3/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 24/2010-सेवा-कर

सा.का.नि. 530(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 76 के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2010 को नियुक्त करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

[फा. सं. बी-1/24/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No: 24/2010-Service Tax

G.S.R. 530(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (A) and (B) of Section 76 of the Finance Act, 2010 (14 of 2010), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2010, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. B-1/24/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 25/2010-सेवा-कर

सा.का.नि. 531(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (105) के उप-खंड (यययत) में निर्दिष्ट कराधेय सेवा को, हवाई परिवहन यात्रियों को नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है :

- (i) एक व्यक्ति जो एक सीमा-शुल्क हवाई अड्डे पर भारत के बाहर एक जगह से आया है और भारत से पारगमन में है, बशर्ते कि वह आप्रवास के माध्यम से पारित नहीं करता है और सीमा-शुल्क सीमा नहीं छोड़ता है और भारत से बाहर एक जगह के लिए अपनी यात्रा जारी रखता है; और
- (ii) विमान आपरेटर द्वारा किसी भी क्षमता में या नियुक्त विमान आरूढ़ व्यक्ति;

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 334/3/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 25/2010-Service Tax

G.S.R. 531(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts air transport of passengers referred to in sub-clause (zzzo) of clause (105) Section 65 of the Finance Act, in respect of persons specified below, from the whole of the service tax leviable thereon under Section 66 of the Finance Act,—

- (i) a person who has arrived at a customs airport from a place outside India and is in transit through India, provided that he does not pass through immigration and does not leave customs area and continues his journey to a place outside India; and
- (ii) a person employed or engaged by the aircraft operator in any capacity on board the aircraft;

2. This notification shall come into force on 1st day of July, 2010.

[F. No. 334/3/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 26/2010-सेवा-कर

सा.का.नि. 532(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है) की धारा 94 की उप-धारा (2) के परन्तुक (अ अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (105) के उप-खंड (यययत) में निर्दिष्ट कराधेय सेवा को, उस पर उदग्रहणीय सेवाकर से छूट देती है :—

(क) टिकट के सकल मूल्य के दस प्रतिशत या सौ रुपये प्रति यात्रा, जो भी कम हो, यात्री भारत में किसी भी वर्ग में यात्रा के लिए;

(ख) टिकट के सकल मूल्य के दस प्रतिशत या पांच सौ रुपये प्रति यात्रा, जो भी कम हो, जो भारत के आरूढ़ इकॉनॉमी वर्ग में अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए;

परन्तु यह छूट उस अवस्था में लागू नहीं होगी जब केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियमावली, 2004 के प्रावधानों के तहत कराधेय सेवाओं के आदानों पर कोई सेनवेट क्रेडिट लिया गया हो;

स्पष्टीकरण : उप-खंड के प्रयोजन के लिए, विमान में इकॉनॉमी वर्ग का मतलब है,—

(i) जहां यात्रा में एक से अधिक वर्ग हैं, वहां के न्यूनतम मानक किराया वाला वर्ग या,

(ii) जहां यात्रा में सिर्फ एक वर्ग है, वही वर्ग

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 334/3/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 26/2010-Service Tax

G.S.R. 532(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (2) of Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the services referred to in clause (zzzo) of sub-section (105) of section 65 of Finance Act, 1994, from so much of service tax as is in excess of,—

(a) ten per cent of the gross value of the ticket or rupees one hundred per journey, whichever is less, for passengers travelling in any class, within India;

(b) ten per cent of the gross value of the ticket or rupees five hundred per journey, which is less, for passengers embarking in India for an international journey in economy class :

Provided that this exemption shall not apply in cases where—

the credit of duty paid on inputs used for providing such taxable service has been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004.

Explanation.—For the purposes of this notification, economy class in an aircraft means,—

- (i) where there is more than one class of travel, the class attracting the lowest standard fare; or
- (ii) where there is only one class of travel, that class.

2. This notification shall come into force on 1st day of July, 2010.

[F. No. 334/03/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 27/2010-सेवा-कर

सा.का.नि. 533(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (105) के उप-खंड (यययत) में निर्दिष्ट कराधेय सेवा को, जो यात्री आसाम या त्रिपुरा या मेघालय या मिजोरम या मणिपुर या नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या पश्चिम बंगाल स्थित बागडोगरा के हवाई अड्डों से यात्रा शुरू या समाप्त करते हैं, उन्हें उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 334/3/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 27/2010-Service Tax

G.S.R. 533(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service referred to in sub-clause (zzzo) of clause (105) of Section 65 of the said Act, for passengers embarking on a journey originating or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh or Assam or Manipur or Meghalaya or Mizoram or Nagaland or Sikkim or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal, from the whole of service tax leviable thereon under Section 66 of the said Act.

2. This notification shall come into force on 1st day of July, 2010.

[F. No. 334/03/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 28/2010-सेवाकर

सा.का.नि. 534(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (105) के उप-खंड (यययज) में निर्दिष्ट कराधेय सेवा को, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और राजीव आवास योजना के संबंध में, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 334/3/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 28/2010-Service Tax

G.S.R. 534(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service of construction of complex referred to in sub-clause (zzzh) of clause (105) of Section 65 of the Finance Act, when provided to Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and Rajiv Awaas Yojana, from the whole of the service tax leviable thereon under Section 66 of the Finance Act.

2. This notification shall come into force on 1st day of July, 2010.

[F. No. 334/03/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 29/2010-सेवाकर

सा.का.नि. 535(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है; भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2006-सेवाकर, तारीख 1 मार्च, 2006, सा.का.नि. 115(अ), तारीख 1 मार्च, 2006, में प्रकाशित हुई थी और 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 7 और 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. 7क और 10क प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"(7क).	(ययद)	वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण	<p>वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (25ख) के उप-खंड (ग) में बिल्डिंग या नागरिक संरचना के संबंध में सेवाओं का परिष्करण करेगा, इस छूट के मामलों में जहां कर योग्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं पूरा करने में लागू नहीं होती ।</p> <p>स्पष्टीकरण : सकल माल और माल की आपूर्ति या मूल्य प्रदान या सेवा प्रदाता द्वारा योग्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाना शामिल होगा ।</p> <p>इस छूट के मामले में जमीन की कीमत खरीददार से अलग बरामद होने पर लागू नहीं होगी</p>	25"
"10(क).	(यययज)	परिसर का निर्माण	<p>वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (30क) के उप-खंड (क) में आवासीय परिसर के संबंध में सेवाओं का परिष्करण करेगा, इस छूट के मामलों में जहां कर योग्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं पूरा करने में लागू नहीं होती ।</p> <p>स्पष्टीकरण : सकल माल और माल की आपूर्ति या मूल्य प्रदान या सेवा प्रदाता द्वारा योग्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाना शामिल होगा ।</p> <p>इस छूट के मामले में जमीन की कीमत खरीददार से अलग बरामद होने पर लागू नहीं होगी</p>	25"

[फा. सं. 334/3/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, अधिसूचना सं. 1/2006-सेवाकर, तारीख 1 मार्च, 2006, सा.का.नि. 115(अ), तारीख 1 मार्च, 2006, द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 09/2010-सेवाकर तारीख 27 फरवरी, 2010 सा.का.नि. 153(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 29/2010-Service Tax

G.S.R. 535(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2006-Service Tax, dated the 1st March, 2006, G.S.R. 115(E), dated the 1st March, 2006, with effect on and from the 1st day of July, 2010, namely :—

In the said notification, in the Table, after S. No. 7 and 10 and the entries relating thereto, the following S. No. 7(a) and 10(a) and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7(a)	(zzq)	Commercial or Industrial Construction	This exemption shall not apply in cases where the taxable services provided are only completion and finishing services in relation to building or civil structure, referred to in sub-clause (c) of clause (25b) of Section 65 of the Finance Act. Explanation. —The gross amount charged shall include the value of goods and materials supplied or provided or used for providing the taxable service by the service provider. This exemption shall not apply in cases where the cost of land has been separately recovered from the buyer by the builder or his representative.	25";
"10(a)	(zzzh)	Construction of Complex	This exemption shall not apply in cases where the taxable services provided are only completion and finishing services in relation to residential complex, referred to in sub-clause (b) of clause (30a) of section 65 of the Finance Act. Explanation. —The gross amount charged shall include the value of goods and materials supplied or provided or used for providing the taxable service by the service provider. This exemption shall not apply in cases where the cost of land has been separately recovered from the buyer by the builder or his representative.	25".

[F.No. 334/3/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

Note :—The principal notification No. 1/2006-Service Tax, dated the 1st March, 2006, was published *vide* number G.S.R. 115(E), dated the 1st March, 2006, and last amended *vide* notification No. 09/2010-Service Tax, dated the 27th February, 2010, published *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 27th February, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 30/2010-सेवा-कर

सा.का.नि. 536(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (एतद्वारा वित्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में अनिवार्य है, एतद्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 की उप-धारा (105) के खंड (यययद) में उल्लिखित सेवाओं को निम्नलिखित के लिए प्रदान किए जाने पर वित्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत उन पर उद्ग्राह्य सेवा कर से पूर्णतया मुक्त करती है :—

- (i) राष्ट्रीय खेल संघों अथवा ऐसे राष्ट्रीय खेल संघों से सम्बद्ध संघों में से किसी संघ द्वारा आयोजित क्रीड़ा एवं खेल टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप जहां सहभागी अथवा व्यक्ति किसी जिले, राज्य अथवा जोन का प्रतिनिधित्व करता है;
- (ii) भारतीय विश्वविद्यालय संघ—अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, भारतीय स्कूल खेल संघ, अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, भारतीय पैरालिम्पिक समिति (शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए), विशेष ओलिम्पिक्स भारत (मानसिक रूप से विकलांगों के लिए) द्वारा आयोजित टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप;

- (iii) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड द्वारा आयोजित टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप;
- (iv) भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा राष्ट्रीय खेल के भाग के रूप में आयोजित टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप;
- (v) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) स्कीम के अंतर्गत आयोजित टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 334/03/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 30/2010-Service Tax

G.S.R. 536(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the services referred to in clause (zzzn) of sub-section (105) of Section 65 of Finance Act, 1994, when provided for :—

- (i) tournaments of championships organized by any of the National Sports Federations or Federations affiliated to such National Sports Federations, where the participating teams or individuals represent any District, State or Zone;
- (ii) tournaments or championship organized by Association of Indian Universities—Inter-University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, Paralympic Committee of India (for the physically challenged), Special Olympics Bharat (for the mentally challenged);
- (iii) tournaments or championships organized by the Central Civil Services Cultural and Sports Board;
- (iv) tournaments or championships organized as part of National Games, by the Indian Olympic Association;
- (v) tournaments or championships organized under Panchayat Yuva Kreedha Aur Khel Abhiyaan (PYKKA) Scheme

from the whole of the Service Tax leviable thereon under Section 66 of the Finance Act.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2010.

[F. No. 334/03/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 31/2010-सेवा-कर

सा.का.नि. 537(अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (एतदपश्चात् वित्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में अनिवार्य है, एतद्वारा बन्दरगाह अथवा विमानपत्तन के अंतर्गत प्रदान किए जाने पर निम्नलिखित सेवाओं को वित्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत उन पर उद्ग्राह्य सेवा कर से पूर्णतया मुक्त करती है :—

- (i) जब जहाज या बोटों या वैसल भारत सरकार के होते हैं (नौ सेना या कोस्ट गार्ड या सीमा-शुल्क सहित परन्तु सरकार अधिग्रहित पीएसयू को छोड़कर);
- (ii) जब जहाज या बोटों या वैसल की मरम्मत जिसे "उत्पादन" कहा जा सकता है और जिसका तात्पर्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 (1994 का 1) की धारा 2 के परन्तुक (ड) के अंतर्गत हो;
- (iii) जल की आपूर्ति;
- (iv) बिजली आपूर्ति;
- (v) औषधालय, अस्पताल, नर्सिंग होम अथवा मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक द्वारा कॉस्मेटिक अथवा प्लास्टिक सर्जरी सेवा को छोड़कर व्यक्तियों का उपचार;
- (vi) वाणिज्यिक शिक्षण अथवा प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को छोड़कर औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल अथवा केन्द्र द्वारा प्रदान की गई सेवाएं;

(vii) अग्निशोमक एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं;

(viii) प्रदूषण नियंत्रण सेवाएं।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 334/03/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 31/2010-Service Tax

G.S.R 537(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the following services when provided within a port or an airport :—

- (i) repair of ships or boats or vessels belonging to the Government of India including Navy or Coast Guard or Customs but does not include Government owned Public Sector Undertakings;
- (ii) repair of ships or boats or vessels where such process of repair amounts to 'manufacture' and has the meaning assigned to it in clause (f) of Section 2 of the Central Excise Act, 1944;
- (iii) supply of water;
- (iv) supply of electricity;
- (v) treatment of persons by a dispensary, hospital, nursing home or multi-speciality clinic (except cosmetic or plastic surgery service);
- (vi) services provided by a school or centre to provide formal education other than those services provided by commercial coaching or training centre;
- (vii) services provided by fire service agencies;
- (viii) pollution control services

from the whole of the Service Tax leviable thereon under Section 66 of the Finance Act.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2010.

[F. No. 334/03/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 32/2010-सेवा-कर

सा.का.नि. 538(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, विद्युत वितरण की कराधेय सेवा को, जो किसी व्यक्ति को किसी वितरण लाईसेंसधारी, विशेषज्ञ-वितरक या कोई अन्य व्यक्ति, जो कि विद्युत वितरण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अधिकृत किया गया हो, द्वारा उपलब्ध कराई जाती है,

उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 356/13/2010-टीआरयू]
के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 32/2010-Service Tax

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as 'the said Finance Act'), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service provided to any person, by a distribution licensee, a distribution franchisee, or any other person by whatever name called, authorized to distribute power under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), for distribution of electricity, from the whole of service tax leviable thereon under Section 66 of the said Finance Act.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 356/13/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 33/2010-सेवा-कर

सा.का.नि. 539(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम भी कहा गया है) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 07/2010-सेवाकर, तारीख 27 फरवरी, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. 151(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, शब्द और अंक 'जुलाई, 2010', के स्थान पर शब्द और अंक 'जनवरी, 2011' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 334/3/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पणः—मूल अधिसूचना सं. 07/2010-सेवाकर, तारीख 27 फरवरी, 2010, सा.का.नि. 151(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. 253(अ), तारीख 30 मार्च, 2010 के जरिए अधिसूचना सं. 20/2010-सेवाकर, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 33/2010-Service Tax

G.S.R. 539(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 07/2010-Service Tax, dated the 27th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 151(E), dated the 27th February, 2010, namely:—

2. In para 2 of the said Notification, for the word and figure 'July, 2010', the word and figure 'January, 2011' shall be substituted.

[F. No. 334/3/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy

Note :—The principal notification No. 07/2010-Service Tax, dated the 27th February, 2010, was published vide number G.S.R. 151(E), dated the 27th February, 2010 and last amended vide Notification No. 20/2010-Service Tax, dated the 30th March, 2010, published vide number G.S.R. 253(E), dated 30th March, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 34/2010-सेवा-कर

सा.का.नि. 540(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम भी कहा गया है) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 08/2010-सेवाकर, तारीख 27 फरवरी, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सं. सा.का.नि. 152(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, शब्द और अंक 'जुलाई, 2010' के स्थान पर शब्द और अंक 'जनवरी, 2011' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 334/3/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पणः—मूल अधिसूचना सं. 08/2010-सेवाकर, तारीख 27 फरवरी, 2010, सा.का.नि. 152(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. 254(अ), तारीख 30 मार्च, 2010 के जरिए अधिसूचना सं. 21/2010-सेवाकर, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010.

No. 34/2010-Service Tax

G.S.R 540(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 08/2010-Service Tax, dated the 27th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 152(E), dated the 27th February, 2010, namely :—

2. In para 2 of the said Notification, for the word and figure 'July, 2010', the word and figure 'January, 2011' shall be substituted.

[F. No. 334/3/2010 -TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

Note :—The principal notification No. 08/2010-Service Tax, dated the 27th February, 2010, was published *vide* number G.S.R. 152(E), dated the 27th February, 2010 and last amended *vide* Notification No. 21/2010-Service Tax, dated the 30th March, 2010, published *vide* number G.S.R. 254(E), dated 30th March, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 35/2010-सेवा-कर

सा.का.नि. 541(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम भी कहा गया है) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 09/2010-सेवाकर, तारीख 27 फरवरी, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. 153(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में, शब्द और अंक 'जुलाई, 2010' के स्थान पर शब्द और अंक 'जनवरी, 2011' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 334/3/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पणः—मूल अधिसूचना सं. 09/2010-सेवाकर, तारीख 27 फरवरी, 2010, सा.का.नि. 153(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010, द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. 255(अ), तारीख 30 मार्च, 2010 के जरिए अधिसूचना सं. 22/2010-सेवाकर, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 35/2010-Service Tax

G.S.R 541(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 09/2010-Service Tax, dated the 27th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 27th February, 2010, namely :—

2. In para 3 of the said Notification, for the word and figure 'July, 2010', the word and figure 'January, 2011' shall be substituted.

[F. No. 334/3/2010 -TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

Note :—The principal notification No. 09/2010-Service Tax, dated the 27th February, 2010, was published *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 27th February, 2010 and last amended *vide* Notification No. 22/2010-Service Tax, dated the 30th March, 2010, published *vide* number G.S.R. 255(E), dated 30th March, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 25/2010-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नै. टै.)

सा.का.नि. 542(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 (1994 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियमावली, 2004 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को "केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2010" कहा जाएगा।

(2) इन नियमों के उपबंध राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियमावली, 2004 के नियम 2 के खंड (अ) में उप-खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :—

"(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 87 के अधीन आने वाले डम्पर या टिप्पर, जो कि सेवा प्रदाता के नाम से पंजीकृत हो, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उप-खंड

(य य य क) तथा (य य य म) में यथानिर्दिष्ट कराधेय सेवा हेतु उपयोग में लाए जाएं ;”।

[फा. सं. 354/3/2009-टीआरयू (पार्ट-1)]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पणः—प्रधान नियमावली की अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि. 600(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004] के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 21/2010-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.), दिनांक 18 मई, 2010 [सा.का.नि. 416(अ), दिनांक 18 मई, 2010] के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 25/2010-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 542(E).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, in rule 2, in clause (a), after sub-clause (B), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

“(C) dumpers or tippers, falling under Chapter 87 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), registered in the name of provider of output service for providing taxable services as specified in sub-clauses (zzza) and (zzzy) of clause (105) of Section 65 of the said Finance Act;”

[F. No. 354/33/2009-TRU(Pt. I)]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 10th September, 2004 vide Notification No. 23/2004-Central Excise (N.T.) dated the 10th September, 2004, published vide G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004 and last amended by Notification No. 21/2010-Central Excise (N.T.) dated 18th May, 2010, published vide G.S.R. 416(E), dated the 18th May, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 01/2010-स्वच्छ ऊर्जा उपकर

सा.का.नि. 543(अ).— वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 83 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 1 जुलाई, 2010 को उस दिन के रूप में नियत करती है, जिस दिन से उपर्युक्त अधिनियम के अध्याय के प्रावधान प्रभावी होंगे।

[फा. सं. 354/72/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 01/2010-Clean Energy Cess

G.S.R. 543(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 83 of the Finance Act, 2010 (14 of 2010), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2010, as the date on which the provisions of Chapter VII of the said Act shall come into force.

[F. No. 354/72/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 02/2010-स्वच्छ ऊर्जा उपकर

सा.का.नि. 544(अ).— वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 83 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के निम्नलिखित प्रावधान, उसमें विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में, कथित वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 83 के अंतर्गत अधिरोपित उपकर के संदर्भ में समान मामलों पर लागू होंगे, नामशः :—

धारा 5क, 6, 9, 9क, 9कक, 9ग, 9घ, 9अ, 11क, 11कक, 11कख, 11कग, 11छछ, 11घघक, 12क, 12ख और 12घ, अध्याय III, VI, VIक, एवं VIख।

[फा. सं. 354/72/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 02/2010-Clean Energy Cess

G.S.R. 544(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 83 of the Finance Act, 2010 (14 of 2010), the Central Government hereby declares that the following provisions of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) relating to the matters specified therein, shall be applicable in regard to like matters in respect of cess imposed under Section 83 of the said Finance Act, namely :—

Sections 5A, 6, 9, 9A, 9AA, 9C, 9D, 9E, 11, 11A, 11AA, 11AB, 11AC, 11B, 11BB, 11C, 11D, 11DD, 11DDA, 12A, 12B, 12C and 12D; Chapters III, VI, VIA and VIB.

[F. No. 354/72/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 03/2010-स्वच्छ ऊर्जा उपकर

सा.का.नि. 545(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, उन सभी वस्तुओं को, जिन पर वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा उपकर उद्ग्राह्य है, उन पर वित्त अधिनियम, 2010 की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्राह्य उपकर से उस सीमा तक छूट प्रदान करती है, जो 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से गणित धनराशि से अधिक है।

[फा. सं. 354/72/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 03/2010-Clean Energy Cess

G.S.R. 545(E).—In exercise of the powers conferred by Section 83 of the Finance Act, 2010 (14 of 2010) read with Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods leviable to the Clean Energy Cess under Section 83 of the said Finance Act, from so much of the cess leviable thereon under the Tenth Schedule to the said Finance Act, 2010 as is in excess of the amount calculated at the rate of Rs. 50 per tonne.

[F. No. 354/72/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 04/2010-स्वच्छ ऊर्जा उपकर

सा.का.नि. 546(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम 2010 (2010 का 14) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्वारा कच्चा कोयला, कच्चा लिग्नाइट और कच्चा पीट को छोड़कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष 2701, 2702, 2703 के अन्तर्गत आने वाले सभी माल को उन पर कथित वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के अन्तर्गत उद्ग्राह्य स्वच्छ ऊर्जा उपकर से छूट प्रदान करती है :

बशर्ते उपर्युक्त छूट इस शर्त के अधीन लागू होगी कि कच्चा कोयला, कच्चा लिग्नाइट या कच्चा पीट स्तर पर जिससे कथित माल उत्पादित या विनिर्मित किया गया है, समुचित स्वच्छ ऊर्जा उपकर अदा किया गया हो।

[फा. सं. 354/72/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 04/2010-Clean Energy Cess

G.S.R. 546(E).—In exercise of the powers conferred by Section 83 of the Finance Act, 2010 (14 of 2010) read with Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling under Central Excise Tariff headings 2701, 2702, 2703 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), other than raw coal, raw lignite and raw peat, from the clean energy cess leviable under Section 83 of said Finance Act :

Provided that the said exemption shall be applicable subject to the condition that applicable clean energy cess has been paid at the stage of raw coal, raw lignite or raw peat from which the said goods are produced or manufactured.

[F. No. 354/72/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 05/2010-स्वच्छ ऊर्जा उपकर

सा.का.नि. 547(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, मेघालय राज्य में स्थानीय जनजातियों द्वारा खान और खनिज (विनियमन एवं विकास), अधिनियम, 1957 तथा कोयला खदान (विकास एवं संरक्षण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत बिना किसी वांछित लाइसेंस/पट्टे के, परम्परागत एवं प्रथागत अधिकारों का प्रयोग करके उत्पादित या निष्कासित सभी माल को वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के अंतर्गत उद्ग्राहणीय स्वच्छ ऊर्जा उपकर से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. 354/72/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 05/2010-Clean Energy Cess

G.S.R. 547(E).—In exercise of the powers conferred by Section 83 of the Finance Act, 2010 (14 of 2010) read with Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods produced or extracted as per traditional and customary rights enjoyed by local tribals in the State of Meghalaya without any license or lease required under any law for the time being in force, from the clean energy cess leviable under Section 83 of the said Finance Act.

[F. No. 354/72/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 06/2010-सी.ई.सी.

सा.का.नि. 548(अ).—वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1**प्रस्तावना****1. लघु शीर्ष, क्षेत्र और आरम्भन :-**

- (1) इन नियमों को स्वच्छ ऊर्जा उपकर नियमावली, 2010 कहा जा सकता है।
- (2) ये सम्पूर्ण भारत में लागू हैं।
- (3) ये पहली जुलाई, 2010 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों के संदर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) "अधिनियम" का अर्थ वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) है।
- (ख) "बोर्ड" का अर्थ केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अंतर्गत गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड है।
- (ग) "उपस्कर" का अर्थ अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत उद्ग्रहित स्वच्छ ऊर्जा उपकर है।
- (घ) "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी" का वही अर्थ होगा जो इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में दिया गया है।
- (ङ) "खान" का वही अर्थ होगा जो इसे खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत दिया गया है।
- (च) "उत्पादक" का अर्थ विनिर्दिष्ट माल के उत्पादन में संलग्न कोई व्यक्ति है और इसमें खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) की धारा 2 के अंतर्गत यथा परिभाषित स्वामी अथवा एजेन्ट शामिल है।
- (छ) "हटाने" का अर्थ खान से विनिर्दिष्ट माल को भेजना है और इसमें ऐसे माल को उठाने के लिए छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए खान के अंतर्गत कारखानागत खपत के लिए भेजना शामिल है।
- (ज) "विनिर्दिष्ट माल" का अर्थ कच्चा कोयला, कच्ची लिग्नाइट और कच्चा पीट है।

अध्याय 2**उपकर का संग्रहण और निर्धारण**

3. पंजीकरण.—उपकर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक उत्पादक तत्काल अधिकतम 30 दिनों के अन्दर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास प्रपत्र 1 में आवेदन कर

क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास स्वयं को पंजीकृत कराएगा।

प्रावधान किया गया कि यदि उत्पादक इन नियमों के लागू होने के बाद किसी भी समय विनिर्दिष्ट माल का उत्पादन करता है तो ऐसा उत्पादक ऐसे उत्पादन के शुरू होने के बाद तीस दिनों के अन्दर पंजीकरण प्राप्त करेगा।

यह भी प्रावधान किया गया कि यदि उत्पादक के पास विभिन्न खानों में उत्पादित ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में केन्द्रीयकृत बिलिंग अथवा लेखा प्रणाली है तो वह इसकी जगह जहां से केन्द्रीयकृत बिलिंग अथवा लेखा किया जाता है उसके परिसरों अथवा कार्यालयों को पंजीकृत करने के विकल्प का चयन कर सकता है।

4. हटाने पर देय उपकर.—प्रत्येक उत्पादक नियम 6 में दिए गए तरीके से विनिर्दिष्ट माल को हटाने पर उद्ग्रहण उपकर या भुगतान करेगा।

5. उपकर का निर्धारण.—उत्पादक विनिर्दिष्ट माल पर देय उपकर का निर्धारण स्वयं करेगा।

6. भुगतान का तरीका.—महीने के दौरान खान से हटाए गए विनिर्दिष्ट माल पर उपकर का भुगतान जिस महीने हटाया गया उसके बाद के दूसरे महीने के 5वें दिन तक करना होगा।

दृष्टांत.—(1) जुलाई, 2010 के महीने के लिए कारखाने से हटाए गए विनिर्दिष्ट माल पर देय उपकर का भुगतान सितम्बर, 2010 के 5वें दिन तक करना होगा।

(2) उत्पादक जिसने नियम 3 के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित अपनी खानों के संबंध में केन्द्रीयकृत पंजीकरण के विकल्प का चयन किया है, वह उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट निर्धारित अवधि तक महीने के दौरान ऐसे सभी खानों से कुल विनिर्दिष्ट माल के हटाने के संबंध में उपकर देयता का भुगतान करेगा।

(3) यदि उत्पादक ने केन्द्र सरकार को एक महीने के लिए उपकर देयता के लिए अपेक्षित राशि से अधिक राशि का भुगतान कर दिया है तो ऐसा उत्पादक भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का समायोजन अगले महीने के लिए उपकर देयता से कर सकता है।

प्रावधान किया गया कि उप-नियम (2) के अंतर्गत भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का समायोजन इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसे अतिरिक्त राशि के भुगतान के कारण है और इन कारणों में कानून की व्याख्या कराधेयता अथवा किसी छूट अधिसूचना का उपयोग शामिल नहीं है।

यह भी प्रावधान किया गया कि यदि उत्पादक अगले महीने की कर देयता से अतिरिक्त राशि का समायोजन नहीं कर पाता है तो वह भुगतान की गई किसी भी अतिरिक्त राशि के प्रतिदाय का दावा दाखिल कर सकता है।

(4) यदि उत्पादक अंतिम तिथि तक उपकर का भुगतान नहीं कर पाता है तो वह अंतिम तिथि के बाद पहले दिन से बकाया राशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11क ख (1944 का 1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(5) यदि उत्पादक नियम 6 में विहित अंतिम तिथि से तीस दिनों के अन्दर भी भुगतान नहीं कर पाता है तो यह समझा जाएगा कि ऐसे विनिर्दिष्ट माल को उपकर के भुगतान के बिना ही क्लियरेंस दे दी गई है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के लागू नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत परिणामों और जुर्माने का अर्थदंड उप-नियम (4) के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त लगाया जाएगा।

(6) नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित उपकर और उप-नियम (4) के अंतर्गत ब्याज की वसूली के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11 के प्रावधान उसी रूप में लागू होंगे जिस रूप में वे सरकार को देय किसी राशि की वसूली के लिए लागू हैं।

स्पष्टीकरण : इस नियम के उद्देश्य के लिए—

- (i) उपकर देयता का भुगतान तभी माना जाएगा जब देयराशि विनिर्दिष्ट तिथि तक केन्द्र सरकार के खाते में जमा कर दी जाए।
- (ii) यदि पंजीकृत व्यक्ति बैंक द्वारा उपकर जमा करता है तो इसके लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत बैंक में चैक जमा करने की तिथि को उपकर जमा करने की तिथि मानी जाएगी, बशर्ते कि चैक का भुगतान हो जाए।

7. रिकार्डों का रखरखाव.—(1) प्रत्येक उत्पादक महीने के दौरान वास्तविक रूप में हटाए गए विनिर्दिष्ट माल की मात्रा जिनको ये दिए गए महीने के दौरान देय उपकर की राशि और भुगतान किए गए कुल उपकर को दर्शाने वाला लेखा रखेगा।

प्रावधान किया गया कि उत्पादक ने नियम 3 के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत पंजीकरण के विकल्प को चुना है और ऐसा उत्पादक उप-नियम (1) में उल्लिखित खान-वार ब्यौरा रखेगा।

(2) हटाए जाने पर देय उपकर की राशि को अगली पूर्ण इकाई में तब्दील किया जाएगा और खेप के वजन को अगले टन के रूप में बदला जाएगा।

8. पंजीकृत परिसर अथवा खान तक पहुंच.—(1) इस नाम पर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी राजस्व के हित की रक्षा के लिए अनिवार्य समझी जाने वाली कोई जांच-छानबीन और निरीक्षण के लिए इस उद्देश्य के लिए इन नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत किसी खान या परिसर में जा सकता है।

(2) प्रत्येक उत्पादक उप-नियम (1) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :—

- (i) विनिर्दिष्ट माल के उत्पादन, भंडारण अथवा विस्थापन के संबंध में कारोबारों की लेखा के लिए तैयार और रखे गए सभी रिकार्ड; और
- (ii) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि सहित वित्तीय रिकार्ड एवं विवरण।

9. उचित दस्तावेजों के अंतर्गत हटाए जाने वाले माल.—(1) खान से कोई भी विनिर्दिष्ट माल, जिन पर उपकर उद्ग्रहित है, हटाया

नहीं जाएगा जब तक कि विनिर्दिष्ट माल की मात्रा और खेप पाने वाले का नाम व पता दर्शाने वाला लिफाफा नहीं लगाया जाए।

10. बीजक अथवा बिल में पृथक रूप से उपकर दर्शाया जाएगा.—उत्पादक द्वारा विनिर्दिष्ट माल के संबंध में तैयार बिल अथवा बीजक में उपकर पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

11. विवरणी दाखिल करना.—प्रत्येक उत्पादक क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास प्रपत्र-II में विवरणी जमा करेगा जिसमें महीने के दौरान हटाए गए विनिर्दिष्ट माल, जिसके संबंध में भुगतान कर दिया गया है, की मात्रा, नियम 6 के अंतर्गत भुगतान की राशि और उस प्रपत्र में विनिर्दिष्ट अन्य विवरण दर्शाए गए हों। साथ ही जिस महीने भुगतान किया गया है उसके 10वें दिन तक उपकर भुगतान का साक्ष्य भी संलग्न किया जाना चाहिए।

प्रावधान किया गया कि यदि उत्पादक ने नियम 3 के अंतर्गत केन्द्रीयकृत पंजीकरण ले लिया है तो प्रपत्र-1 में विवरणी में खान-वार सूचना होनी चाहिए।

12. सामान्य जुर्माना.—इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के लिए, जहां किसी जुर्माने का प्रावधान नहीं है, दस हजार रुपए तक का जुर्माना और उक्त माल जिसके लिए अपराध किया गया है, की जब्ती का प्रावधान होगा।

[फा. सं. 354 /72/2010-टीआरयू]

के. एस. बी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

प्रपत्र-1

विनिर्दिष्ट माल को हटाने के लिए मासिक विवरणी
(नियम 11 देखें)

उत्पादक का नाम	:				
पूरा पता	:				
पंजीयन संख्या	:				
माह	:				
विनिर्दिष्ट माल का विवरण	:				
माह के	प्रति टन	बिल के	संदत कुल	अभियु-	
दौरान	उपशुल्क की	अनुसार संदेय	उपकर	क्तियां	
हटाए गए	दर (प्रति-	कुल उपकर	(रुपए)		
विनिर्दिष्ट	टन रुपए)	(रुपए)			
माल की					
मात्रा (एम					
टी में)					

टिप्पणी :—ऐसे मामले में जहां उत्पादक ने नियम 3 के अंतर्गत केन्द्रीयकृत पंजीयन प्राप्त कर लिया है, वह प्रत्येक खान के संबंध में उपर्युक्त ब्यौरा उपलब्ध कराएगा।

मैं/हम एतद्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि इन विवरणों में दी गई सूचना हर प्रकार से सत्य एवं सही है।

(स्पष्ट अक्षरों में नाम तथा पंजीकृत व्यक्ति अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 06/2010-Clean Energy Cess

G.S.R. 548(E).—In exercise of the powers conferred by Section 84 of the Finance Act, 2010 (14 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

Chapter 1**PRELIMINARY****1. Short title, extent and commencement.—**

(1) These rules may be called the Clean Energy Cess Rules, 2010.

(2) They extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on the 1st day of July, 2010.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Finance Act, 2010 (14 of 2010);
- (b) “Board” means the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Board of Revenue Act, 1963 (54 of 1963);
- (c) “cess” means the Clean Energy Cess levied under Section 83 of the Act;
- (d) “Central Excise Officer” shall have the meaning assigned to it in the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);
- (e) “mine” shall have the meaning assigned to it under Mines Act, 1952 (32 of 1952);
- (f) “producer” means any person engaged in the production of specified goods and includes a owner or agent as defined under Section 2 of the Mines Act, 1952 (32 of 1952);
- (g) “removal” means despatch of specified goods from a mine and shall include despatch of such goods for captive consumption within that mine for any purpose other than for raising of such goods;
- (h) “specified goods” means raw coal, raw lignite and raw peat.

Chapter 2**COLLECTION AND ASSESSMENT OF CESS**

3. Registration.—Every producer who is liable to pay cess shall get registered immediately with the jurisdictional Central Excise Officer but not later than a period of thirty days from the date of commencement of these rules by making an application to the jurisdictional Central Excise Officer :

Provided that where a producer commences production of the specified goods at any time after the commencement of these rules, such producer shall obtain registration within thirty days from the commencement of such production :

Provided further that where a producer has a centralized billing or accounting system in respect of such

specified goods produced at different mines, he may, instead, opt for registering only the premises or office from where such centralized billing or accounting is done.

4. Cess payable on removal.—Every producer shall pay the cess leviable on the removal of the specified goods in the manner provided in rule 6.

5. Assessment of cess.—The producer shall himself assess the cess payable on the specified goods.

6. Manner of payment.—(1) Cess on the specified goods removed from the mine during a month shall be paid by the 5th of the second month, following the month in which the removals were made :

Illustration.—Cess payable on specified goods removed from the factory for the month of July, 2010 shall be paid by the 5th of September, 2010.

(2) A producer who has opted for centralized registration in respect of its mines located at different places under rule 3, shall discharge the cess liability in respect of the aggregate removal of specified goods from all such mines effected during a month by the stipulated period specified in sub-rule (1).

(3) Where a producer has paid to the credit of the Central Government any amount in excess of the amount required to be paid towards cess liability for a month, such producer may adjust such excess amount paid by him against the cess liability for the next month :

Provided that the adjustment of excess amount paid under sub-rule (2) shall be subject to the condition that such excess amount paid is on account of reasons not involving interpretation of law, taxability, or applicability of any exemption notification :

Provided further that the producer may, instead, file a refund claim for any excess amount of cess paid if such producer fails to adjust the excess amount against the cess liability for the next month.

(4) Where any producer fails to pay the cess by the due date, he shall be liable to pay the outstanding amount along with interest at the rate specified by the Central Government under section 11AB of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) on the outstanding amount for the period starting from the first day after the due date till the date of the actual payment of the outstanding amount.

(5) Where any producer defaults in payment beyond thirty days from the due date as specified in rule 6, such specified goods shall be deemed to have been cleared without payment of cess and the consequences and penalties under these rules and provisions of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) as have been made applicable, shall follow in addition to payment of interest under sub-rule (4).

(6) The provisions of Section 11 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) shall be applicable for recovery of the cess as assessed under rule 5 and the interest under sub-rule (4) in the same manner as they are applicable for recovery of any sums payable to the Central Government.

Explanation.—For the purposes of this rule,—

- (i) Cessliability shall be deemed to be discharged only if the amount payable is credited to the account of the Central Government by the specified date;
- (ii) Where the registered person deposits cess by cheque, the date of presentation of the cheque in the bank designated by the Board for this purpose shall be deemed to be the date on which the cess has been paid subject to realization of the cheque.

7. Maintenance of records.—(1) Every producer shall maintain accounts showing the quantity of specified goods actually removed during a month, particulars to whom these were removed, the amount of cess payable during a month and the total amount of cess paid :

Provided that where a producer has opted for centralized registration under rule 3, such producer shall maintain mine wise details mentioned in the sub-rule (1).

(2) The amount of cess payable on any removals shall be rounded off to the nearest rupee and the actual weight of a consignment shall be rounded off to the nearest tonne.

8. Access to registered premises or mine.—(1) An officer empowered by the Commissioner in this behalf shall have access to any mine or premises registered under these rules for the purpose of carrying out any scrutiny, verification and checks as may be considered necessary to safeguard the interest of revenue.

(2) Every producer shall furnish to the officer empowered under sub-rule (1),—

- (i) all records prepared and maintained for accounting of transactions in regard to production, storage or removal of specified goods; and
- (ii) financial records and statements including cost audit reports etc.

9. Goods to be removed under proper documents.—No specified goods leviable to cess shall be removed from a mine except under cover of a document indicating the quantity of specified goods and the name and address of the consignee.

10. Cess shall be shown separately in the invoice or bill.—Cess shall be shown separately by the producer in the bill or invoice raised in respect of specified goods.

11. Filing of return.—Every producer shall submit to the Jurisdictional Central Excise Officer, a return in Form-I showing the quantities of specified goods removed during the month in respect of which the payment has been made, the amount paid under rule 6 and other particulars specified in that form enclosing the evidence of payment of cess not later than 10th day of the month in which the payment has been made :

Provided that in the case of a producer who has obtained centralized registration under rule 3, the return in Form-I shall contain mine-wise information.

12. General penalty.—Whoever contravenes any of the provisions of these rules shall be liable to pay a penalty which may extend to ten thousand rupees and confiscation of the goods in question in respect of which the contravention is made, if no penalty is provided elsewhere.

[F. No. 354/72/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

FORM I

Monthly return for removal of specified goods (See Rule 11)

Name of Producer	:	
Full Address	:	
Registration Number	:	
Month	:	
Description of specified goods	:	
Quantity of specified goods removed during the month (in MT)	Rate of cess per tonne (Rs. per tonne)	Total cess payable as per(Rs.) billing (Rs.)
		Total remarks cess paid (Rs.)

Note: In case where a producer has obtained centralised registration under rule 3, he shall provide the above details in respect of each mine.

I/we hereby solemnly declare that the information given in this return is true, correct and complete in every respect.

(Name in capital letters and signature of the registered person or his authorised agent)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 28/2010-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 549(अ).—वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और 93 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल को कथित वित्त (सं. 2) अधिनियम की कथित धारा 91 और 93 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. 354/72/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 28/2010-Central Excise

G.S.R. 549(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Sections 91 and 93 of the Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so

to do, hereby exempts all goods specified in the Tenth Schedule to the Finance Act, 2010 (14 of 2010) from the Education Cess Leviable thereon under the said Sections 91 and 93 of the said Finance (No. 2) Act.

[F.No. 354/72/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सं. 29/2010-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 550(अ).—वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 और 138 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्वारा वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल को कथित वित्त अधिनियम, 2007 की कथित

धारा 136 और 138 के अंतर्गत उनपर उद्गाह्य उच्च शिक्षा उपकर से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. 354/72/2010-टीआरयू]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

No. 29/2010-Central Excise

G.S.R. 550(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Sections 136 and 138 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods specified in the Tenth Schedule to the Finance Act, 2010 (14 of 2010) from the Higher Education Cess Leviable thereon under the said Sections 136 and 138 of the said Finance Act.

[F.No. 354/72/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.